

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 12, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अक्टूबर 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद् के पद पर पदस्थ करता है.

श्री राणा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद् के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन तथा संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद् को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उप सचिव तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 20-90/2019/11/6.—चूँकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

1. अतएव राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर 2020 के दिनांक से अंकित संशोधन क्रमांक-19 (उन्नीस) के अनुसरण में राज्य में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए जोड़े गये परिशिष्ट-(6.21) के अनुसार “छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट-अप पैकेज” के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रावधान, नियम एवं शर्तें लागू की जाती हैं :—

छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट-अप पैकेज

1. **परिभाषाएं :—** स्टार्ट-अप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अनुसार किसी एकक/इकाई को निम्नानुसार स्टार्ट-अप माना जायेगा :—

- (क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।
- (ख) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एकक/इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपये से अधिक न हो।
- (ग) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन की सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी एकक/इकाई को “स्टार्ट-अप” नहीं माना जाएगा।

2. **स्पष्टीकरण :—**

- 1. कोई एकक/इकाई अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक होने पर “स्टार्ट-अप” के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 2. एकक/इकाई का अर्थ है—कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत)।
- 3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषा में किये जाने वाले संशोधन सहित) किए अनुसार मान्य होगी।

4. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ही मान्य किया जाएगा.
5. औद्योगिक नीति 2019-24 में दिए गए प्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्ट-अप इकाईयों को अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप पोर्टल में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है.

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्टअप इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 में कंडिका 12 में दिए गए प्रावधानों के तहत स्टार्ट-अप पैकेज लागू किया जाता है तथा ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :—

1. **ब्याज अनुदान :—**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा		
		अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	7	50	20
	ब	8	50	25
	स	9	60	35
	द	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	6	35	35
	ब	7	40	45
	स	9	60	55
	द	11	70	55

2. **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :—**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)
सूक्ष्म उद्योग	अ	35	15
	ब	40	18
	स	45	20
	द	55	24

3. **नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :—** (केवल लघु, मध्यम स्टार्टअप इकाईयों हेतु)

क्षेत्र की श्रेणी	प्रतिपूर्ति का विवरण
(1)	(2)
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत.

(1)	(2)
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत.
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत.
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत.

4. विद्युत शुल्क छूट :—

क्षेत्र की श्रेणी (1)	विवरण (2)
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

5. भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट.

6. सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट.

7. (1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान—मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रुपये 2.50 लाख.

(2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान—प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 05 लाख.

(3) तकनीकी पेटेंट अनुदान—पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10 लाख.

(4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान—प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10 लाख.

(5) औद्योगिक पुरस्कार योजना—स्टार्ट अप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि रु. 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

(6) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान—छत्तीसगढ़ के स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त एक अथवा अधिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशॉप/संगोष्ठी/प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रु. 15,000/- एवं देश के बाहर रु. 30,000/- तथा रु. 1,00,000/- प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी.

8. उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू-प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी.

9. छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षों के लिये श्रम कानूनों में Self Certification के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी.
10. स्टार्ट-अप पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :—
 - 10.1 **किराया अनुदान**— छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराए के भवन में स्टार्ट अप एकक/इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रु. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रु. 8000/- की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी.
 - 10.2 **इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान**— छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, इनक्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का किराया का भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रु. 8/- प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रतिमाह अधिकतम राशि रु. 8,000/- की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी.
11. स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन हेतु इनक्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान :—
 - 11.1 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इनक्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 50 लाख.
 - 11.2 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इनक्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) में किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 50 लाख.
 - 11.3 इनक्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रु. 03 लाख प्रति वर्ष.
12. राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी.
13. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात् पात्रता अनुसार सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी.
14. स्टार्ट-अप एकक/इकाईयों को विभिन्न आरंभिक कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष संपर्क हेतु उद्योग संचालनालय में स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा जो कि उद्देश्य के अनुरूप स्टार्टअप इकाईयों को सहायता करेगा.
15. स्टार्ट-अप एकक/इकाईयों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाएंगे.
16. स्टार्ट-अप एकक/इकाईयों की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए संपर्शिक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है.

17. प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों की स्थापना हेतु कैप के आयोजन एवं शुश्रूषा हेतु इन्क्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा.
18. प्रदेश में स्टार्ट-अप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिए समय-समय पर स्टार्टअप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्टअप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो.
19. प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्टअप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा.
20. स्टार्ट-अप इकाईयों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके.
21. उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी.
22. इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्टअप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे. इसी प्रकार से भारत शासन से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त है तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे.
23. इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्टअप इकाईयों को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में हो.
24. इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात् उसे 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रुपये 100 करोड़ से अधिक न हुआ हो. इसका अर्थ यह है कि 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रुपये 100 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी.
25. पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा.
26. **अन्य कार्यकारी निर्देश :—**
 - (26.1) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई मूल अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधान यथा-आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी.
 - (26.2) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित स्टाम्प ड्यूटी छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा-आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिककर (पंजीयन) विभाग के द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी.

- (26.3) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी मूल अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा-आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी.
- (26.4) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित इस पैकेज में निर्धारित आधिक्य में प्रदान दिये जाने वाली घोषित विद्युत शुल्क छूट हेतु समस्त प्रशासनिक नियम, शर्तें एवं प्रावधान योजना के मूल क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधान यथा-आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र एवं स्वीकृति तथा वितरण/प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया आदि योजनाओं की छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप होगी.
27. **स्वप्रेरणा से निर्णय :**— राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा.
28. **कार्यकारी निर्देश :**— अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे. अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा.
29. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.
30. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.
31. **योजना का क्रियान्वयन :**— योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक एफ 1-02/2021/दो-गृह/भापुसे (पार्ट-2).—राज्य शासन एतद्वारा श्री चव्हान किरण गंगाराम (भापुसे-2018), परि.भापुसे जिला-बिलासपुर, को तत्काल प्रभाव से नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 अक्टूबर 2021

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2022 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-114/गृह-सी/परीक्षा/2021.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 24 जनवरी, 2022 से सोमवार 31 जनवरी, 2022 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अम्बिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 24-01-2022

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	Paper-1, "Electrical Laws (without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
सोमवार, दिनांक 24-01-2022		
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	Paper-2, "Earthing and Electrical Safety (without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 25-01-2022

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“बी”.	
11.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“सी”.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
मंगलवार, दिनांक 25-01-2022		
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	प्रश्न पत्र 4-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों की सहायता से), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	

बुधवार, दिनांक 26-01-2022 को शासकीय अवकाश

(1)	(2)	(3)
गुरुवार, दिनांक 27-01-2022		
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
63.	Paper-5, “Switchgear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 27-01-2022		
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	Paper-6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 28-01-2022

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 28-01-2022		
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शनिवार, दिनांक 29-01-2022		
45.	प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
शनिवार, दिनांक 29-01-2022		
51.	प्रश्न पत्र भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
रविवार, दिनांक 30-01-2022 को शासकीय अवकाश		
सोमवार, दिनांक 31-01-2022		
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

नोट :-

- सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रमाण पत्रों को गृह विभाग, सी-अनुभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें। संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-12-2021 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।
5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव।

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Natar, Nava Raipur

Nava Raipur, the 25th September, 2021

F. No. 10042/2719/XXI-B/C.G./21.—The State Government, on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh vide their Memo No. 707/II-2-101/2001 (Pt. II)/Confdl./2021 dated 24th September, 2021, hereby, withdraws the services of Shri Anil Kumar Pandey, Member of Higher Judicial Service and presently posted as X Additional District and Sessions Judge, Raipur from High Court of Chhattisgarh, places him under Law and Legislative Affairs Department on deputation and appoints him as Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Raipur from the date he assumes charge of the office.

क्रमांक 10042/2719/21-ब/छ.ग./2021.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 707/II-2-101/2001 (Pt. II)/Confdl./2021 बिलासपुर, दिनांक 24-09-2021 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के अनुपालन में, श्री अनिल कुमार पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा, वर्तमान पदस्थापना दशम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की सेवाएं, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापस लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के अधीन प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से उन्हें नियुक्त करता है।

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM KUMAR TIWARI, Principal Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 8 अक्टूबर 2021

प्ररूप-1
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/2625/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2021.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			एकड़ में	हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
बलरामपुर- रामानुजगंज	वाड्डफनगर	मानपुर	4.86	1.97	कुकझरिया व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण ग्राम मानपुर.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई 30-10-2021 को समय 11.00 बजे (स्थान) पंचायत भवन मानपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कुकझरिया व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण ग्राम मानपुर.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	कुल 14 खातेदार/परिवार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	राशि 129.11 लाख (एक करोड़ उनतीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र.
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	कुकझरिया व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से 200 हे. खरीफ एवं 80 हे. रबी कुल 280 हे. क्षेत्र में फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. मानपुर के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये — भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में दर्शाए गए तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 500000/- (पांच लाख रु. मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	(1)	(2)
रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2021	1/433/1	0.203
	618/1/क	0.035
	290/6	0.019
	311/2/क	0.004
	1/530/5	0.024
	1/354/2/क	0.425
	1/586/14/क	2.468
	1/569/ख	0.041
	1/329/1/ख/2	0.650
	1/361/3/ख	0.054
	613/4/ख	0.023
	761/1	0.136
	4/1	0.041
	1/391/4	0.295
	764/8	0.059
	533/1	0.344
	1/368/1/ख	0.364
	1/346/3/ख	0.678
	1/425/ग	0.680
	1/439/2	0.498
	575	0.255
	705/5	0.356
	1/558/1/ग	0.091
	1/560/5	0.009
	1/371/4/क	0.194
	779/1	0.137
	776	0.129
	1/339/क/2	0.165
खसरा नम्बर	रकबा	
	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
1/534/2	0.711	
1/546/1/ख	0.024	

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जशपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-215.586 हेक्टेयर

(1)	(2)	(1)	(2)
1/440/4	0.028	1/391/3	0.170
614/2	0.050	1/180/4/1	0.010
1/329/2/ख/1	0.280	1/464/6	0.039
1/408/1/ग	0.031	1/538/1	2.428
1/434/5	0.324	1/538/6	0.024
1/329/1/ख/4	0.361	1/513	0.109
1/336/2/क	1.214	1/546/1/घ	0.026
513/1/ग	0.045	1/474/3	0.024
1/243/1/ख	0.066	1/383/2	0.409
1/428/3/ख	0.304	237/8	0.020
1/537/6/क	0.213	1/423/1	0.121
1/329/1/ख/6	0.361	571/1	0.042
705/1/क	0.140	1/440/2	0.028
287/1/ख	0.081	618/2	0.150
1/329/1/क	0.783	534/1	0.077
1/374/2/क	0.237	1/562/ड	0.024
1/558/1/क	0.093	506	0.368
1/588/1/ख	0.186	841	0.162
759/1/ख	0.037	1/243/1/ग	0.067
1/452	0.081	1/546/1/ग	0.026
618/4/ख	0.050	1/361/3/घ	0.054
1/545/3	0.247	618/4/ग	0.050
834/3/ग	0.054	760/1/घ	0.029
543/1	0.203	291	0.057
833/1	0.071	534/2/क	0.038
1/356/3	0.096	769/2/क	0.255
574/1	0.038	1/430/6	0.142
1/482/1/ख	0.029	1/425/क	0.648
1/430/2	0.138	1/562/ग	0.073
611/1	0.053	1/368/1/ग	0.364
1/339/1/क/6	0.082	759/2/2	0.026
1/329/2/ख/2	0.138	1/560/7	0.027
1/464/5	0.039	209/1	0.183
1/443/1	0.032	613/4/क	0.023
1/556/क	0.154	1/530/6	0.024
1/569/क	0.041	1/538/3	0.074
1/338/4	0.129	1/538/7	0.074
1/180/5	0.010	1/421/1घ	0.649
611/4/ख	0.016	1/588/2/क	0.249
759/1/क	0.036	1/584/2/क	0.694
1/435/1, 1/433/1	0.251	759/3	0.084
1/472/2	0.105	317/1/1	0.004
543/2	0.202	1/479	0.138
1/438/घ	0.036	1/180/2	0.054
1/356/4	0.096	283/2	0.032
599/2	0.027	834/2	0.132

(1)	(2)	(1)	(2)
1/428/2/घ	0.393	574/3	0.039
1/573/ड	0.048	1/464/7	0.117
518	0.154	1/472/1/क	0.024
1/16/4/क	0.013	1/551	0.142
1/421/1/ग	0.649	1/537/6/घ	0.212
1/584/4/ग	0.208	1/421/1/ख	0.650
283/4	0.028	1/538/5	0.024
1/454/2/क	0.023	839/1	0.045
1/326/1	0.094	1/535/1/घ	0.607
602	0.030	1/458/ग	0.316
1/473/3	0.077	770/2	0.065
1/178/1	0.077	237/7	0.024
1/554/1, 1/555/1	0.304	1/434/3	0.146
1/428/5	0.243	551/1	0.052
1/573/ग	0.109	1/408/2	0.093
513/1/ख	0.045	613/2	0.069
705/4	0.233	1/493/1	0.020
1/412/1/क	0.101	1/514/क	0.061
764/1	0.081	1/361/4/ख	0.054
1/433/4	0.204	1/336/3	1.574
1/560/6	0.009	1/558/1/ख	0.091
1/538/4	0.024	1/535/1/ग	0.607
1/418/3	1.173	1/537/6/ग	0.213
1/482/1/घ	0.028	613/4/ग	0.023
1/428/2/ख	0.718	1/512/1/क	0.058
769/2/ख	0.116	236	0.016
1/438/ग	0.036	1/493/2/क	0.010
759/2/1	0.053	534/3	0.077
1/489/1	0.242	1/430/4	0.130
1/361/2	0.162	534/2/ख	0.039
611/2	0.049	1/514/ग	0.057
593	0.398	1/336/4	0.524
1/425/ड	0.231	317/1/2	0.009
275/3	0.036	1/530/7	0.074
1/339/क/1	0.165	684/1	0.107
1/557/3/ख	0.127	1/344/ख	0.040
1/482/1/ग	0.028	1/180/4/2	0.010
1/433/3	0.203	611/3	0.053
611/4/ग	0.017	1/530/4	0.024
1/460/क	0.407	1/560/3	0.027
1/361/3/ग	0.054	1/456	0.057
1/477/2/क	0.014	684/2	0.107
1/493/3	0.021	283/3	0.028
1/178/2	0.081	1/86/2/क	0.336
1/570	0.117	1/243/1/क	0.457
1/476/ग	0.089	1/268	0.040
277	0.069	1/325/2	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
1/342/ग	0.971	1/525	0.040
1/345	0.142	1/528	0.097
1/352	1.181	1/534/1	2.340
1/371/3	0.259	1/537/2/क	2.715
1/383/1	0.558	1/438/ख	0.019
1/385/ख	0.243	1/449/2	0.009
1/390/ख/2	0.222	1/560/4	0.009
1/393/ख	0.291	1/464/3	0.117
1/398/2	0.380	1/339/क/3	0.082
1/411/क	6.703	1/489/2	0.243
1/415/1/क	0.414	1/440/3	0.028
1/427	0.299	618/3	0.198
1/453/क	0.062	1/242/क	0.093
1/461/ग	0.344	1/244/ग	0.364
1/482/1/क	0.028	1/274	0.069
1/509	0.057	1/328	0.858
1/524	0.069	1/346/3/क	0.678
1/527	0.073	1/370/1	0.105
1/533	6.191	1/374/1	0.202
1/537/2	5.018	1/384	0.364
839/2	0.045	1/388/ख	0.251
1/408/5	0.024	1/392	0.700
1/465/1	0.470	1/395	0.324
760/1/ड	0.029	1/404	0.563
1/329/1/ख/3	0.361	1/413/4/क	3.538
1/326/6	0.094	1/424/क/1	0.658
316/1	0.004	1/433/2	0.203
322	0.117	1/458/क	0.295
1/238	0.130	1/478	0.109
1/244/ख	0.121	1/508/2/क	0.146
1/271	0.093	1/522	0.028
1/327	0.773	1/526	0.036
1/343/2/क	0.067	1/529	1.457
1/346/2/क	0.339	1/535/1/क	2.942
1/354/1	0.470	1/537/3/ख	2.716
1/371/5	0.113	760/1/ख	0.044
1/383/3	0.267	1/568/2	0.020
1/388/क	0.636	1/563/1	0.425
1/390/ग	2.440	1/530/3	0.074
1/393/ग	0.579	290/3	0.020
1/399	1.060	293/2	0.109
1/411/ख	2.237	1/449/1	0.028
1/415/2	0.833	1/537/6/छ	0.212
1/428/ग	0.713	1/242/ख	0.275
1/453/ख	0.063	1/267	0.113
1/473/1	0.279	1/277	0.032
1/491	0.061	1/342/क	1.943
1/510	0.097		

(1)	(2)	(1)	(2)
1/344/क	0.045	1/376	0.085
1/346/4	1.356	1/421/1/क	0.648
1/371/1	0.121	1/537/5	3.173
1/378	0.206	1/537/9/क	2.298
1/385/क	0.121	1/542, 1/570/ड	0.101
1/388/ग	0.320	1/561	0.304
1/393/क	0.870	1/572	0.210
1/396	1.578	1/578/ग	0.376
1/405	0.551	1/584/4/क	0.208
1/413/4/ख	3.804	1/587/6/ख	0.813
1/424/ख/1	0.657	287/4	0.057
1/446	0.089	1/240/ग	0.195
1/461/क	0.340	1/270	0.146
1/481	0.154	1/537/4/घ	0.388
1/508/2/घ	0.073	1/354/2/ख	0.142
1/523	0.077	1/370/2/ख	0.057
1/526/589/क	0.263	1/387/1	0.672
1/532/2	1.384	492/2	0.026
1/536	4.856	541/1	0.518
1/537/4/क	0.393	1/434/1/क	0.141
1/537/4/ग	0.393	491/2	0.160
1/537/8	5.836	523	0.291
1/541	0.186	285	0.214
1/552/1	0.082	709/2	0.025
1/567	0.182	237/5	0.045
1/578/ख	0.372	1/584/6/क	0.479
1/583/1	1.534	1/425/ख	0.226
1/587/6/क	1.623	1/177	0.121
1/588/4	1.117	1/343/1/ग	0.067
515/4	0.021	1/350/2	0.494
1/266	0.093	1/387/2	0.607
1/461/ड	0.340	1/428/2/क	0.717
1/435/2, 1/436/2	0.251	1/537/6/ख	0.213
1/369/2/ख	0.072	1/538/2	2.432
614/1	0.833	1/543	0.077
491/1	0.182	1/565	0.239
1/380/2	0.587	1/574/ख	0.036
1/391/1/क	0.211	1/579	3.654
286/2	0.085	1/586/2	0.543
304	0.494	1/587/7	3.399
832	0.037	237/4	0.016
519	0.644	1/241	0.174
509/2	0.069	1/275	0.158
1/507/1	0.425	1/574/क	0.049
759/1/ग	0.011	1/354/3/ख	0.121
275/1	0.041	1/326/2	0.043
1/322/2	0.033	286/1	0.085
1/350/1	0.490		

(1)	(2)	(1)	(2)
711/1	0.149	1/562/क	0.073
1/548	0.995	1/584/4/घ	0.092
1/487/1	0.012	513/1/क	0.045
492/1	0.025	522/1/ख	0.061
531	0.249	1/577/ख	0.567
490	0.321	290/5	0.020
542/1	0.138	1/325/1	0.025
237/6	0.036	1/494/1	0.014
1/584/7/क	0.405	510/1	0.081
1/562/ख	0.025	1/557/1/ख	0.251
1/178/4	0.077	1/381/1	2.403
1/346/1/ग	0.339	1/569/ग	0.040
1/372	1.372	325/1	0.022
1/401	1.623	1/530/1	0.074
1/458/ख, 1/459, 1/475	0.316	324	0.169
1/537/7	10.886	1/467/क	0.319
1/539/3	1.052	1/537/9/ख	0.573
1/546/1/क	0.025	1/476/क	0.129
1/566	0.267	1/535/1/ख	0.607
1/575	5.871	1/564	0.219
1/580	1.457	1/588/2/ख	0.289
1/586/6/ट	1.214	599/1	0.027
1/588/3/क	0.559	769/1/क	0.059
510/4	0.081	514/2	0.081
1/244/क	0.243	1/408/1/घ	0.016
1/290	0.068	1/583/2	1.534
1/438/क	0.018	1/521/3	0.668
1/367	0.673	515/1	0.020
1/338/1	0.129	1/330	0.704
289	0.109	507	0.304
808	0.833	1/577/क/3	0.263
705/2/क	0.450	557/5	0.024
293/1	0.130	1/558/2	0.405
1/448	0.032	536	0.066
532	0.170	1/371/2/ख	0.075
517	0.105	554/3/ख	0.024
609/1	0.049	1/477/2/ख	0.014
1/337	0.802	1/554/4, 1/555/4	0.170
761/3	0.137	1/573/क	0.138
1/573/ख	0.049	1/336/1	0.525
1/322/1	0.032	237/2	0.024
1/346/1/घ	0.339	1/323/क	0.327
1/373	0.837	1/329/1/ख/5	0.361
1/416	1.412	618/1/घ	0.036
1/463/क/3	0.141	288	0.093
1/474/1	0.020	237/1	0.093
1/514/ख	0.057	1/490	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
1/353/1	2.428	1/355/2	0.202
573	0.603	1/323/ग/3	0.062
1/433/5	0.204	1/537/6/ड	0.212
1/464/4	0.039	287/1/क	0.057
1/336/2/ख	0.049	618/1/ख	0.063
516/3	0.154	1/411/घ	2.237
1/374/2/ख, 1/375/2/ख	0.079	1/379/2/ख	0.047
1/493/2/ख	0.010		
1/559/2	0.186	योग	525 215.586
1/584/4/ख	0.208		
1/368/1/क	0.364	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण हेतु.	
1/494/2	0.014		
1/463/ख	0.154		
1/339/क/5	0.083	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
834/3/घ	0.031		
1/484/2	0.061		
237/3	0.020	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
520	0.591	भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 13 अक्टूबर 2021

क्रमांक/12917/अधीक्षक/2021.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुये जिला मुख्यालय में पदस्थ/कार्यरत निम्नांकित कॉलम नंबर 2 में दर्शित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 3 में दर्शाये अनुसार कार्य संपादित करने हेतु एतद्वारा अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्य सौंपा जाता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	सौंपे गए कार्य का विवरण (3)
1.	श्री सुनील कुमार नायक (रा.प्र.से.) संयुक्त कलेक्टर (अपर कलेक्टर का प्रभार)	<p>(अ) दाण्डिक :—</p> <p>अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कोरबा (सम्पूर्ण जिला)</p> <ul style="list-style-type: none"> राजस्व अनुविभाग/तहसील के अधीनस्थ न्यायालयों एवं कार्यालयों की व्यवस्था के अनुसार निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण. <p>(ब) प्रभारी अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> पासपोर्ट <p>(स) कार्यालयीन नोडल अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय निर्वाचन एवं सामान्य निर्वाचन वित्त स्थापना नजूल शाखा लायसेंस शाखा भू-अभिलेख शाखा

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> ● वरिष्ठ लिपिक शाखा ● अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा ● व्यवहारवाद शाखा ● जनगणना ● छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 यथा संशोधित अधिनियम 2015 ● चिप्स/लोक सेवा केन्द्र/एन.आई.सी. ● नगर सेना ● लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा के उत्तर समय पर भिजवाना. ● शिकायत शाखा <ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष कक्ष 2. जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं पीजीएन 3. मुख्यमंत्री जनदर्शन (जन-चौपाल) एवं कलेक्टर जनदर्शन (जन-चौपाल). ● राजस्व आपदा प्रबंधन शाखा एवं कोविड 19 के प्रकरण, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति आदेश पारित करना. ● संजीवनी कोष के प्रकरणों में भाग-2 पर/डॉ. खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना कलेक्टर की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत. ● उपरोक्त शाखाओं/कार्यालयों की नस्तियों का परीक्षण उपरांत कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे. ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य
		<p>(द) विविध नोडल अधिकारी :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सत्कार शाखा के कार्यों पर मार्गदर्शन एवं नियंत्रण ● प्रधानमंत्री सड़क योजना/मुख्यमंत्री सड़क योजना ● राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/लोक निर्माण (भवन-सड़क)/सेतु निर्माण ● राजीव गांधी आश्रय योजना ● जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी ● खाद्य शाखा ● आदिवासी विकास विभाग ● गृह निर्माण मंडल ● श्रम विभाग ● महिला एवं बाल विकास विभाग ● शिक्षा विभाग ● वक्फ बोर्ड ● होमगार्ड ● नागरिक आपूर्ति निगम ● मार्कफेड
		<p>(ई) निम्नलिखित शाखाओं की नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण करेंगे.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● शासकीय कर्मचारियों के लिए उत्तराधिकार/संरक्षण प्रमाण-पत्र जारी करना.

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> ● तहसीलदार/अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियों, जिला कार्यालय स्तर के कार्यालय सहायक ग्रेड-2 एवं 3 व भृत्य के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयक तथा सामान्य भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति में अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति एवं अवकाश स्वीकृति. ● तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (वित्त एवं भू-अभिलेख) के सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि से आंशिक/अग्रिम आहरण की स्वीकृति. ● सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक/लिपिक) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि/समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि भुगतान. ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कलेक्टर की अनुमति आवश्यक हो. ● शासन के नियमों व निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पी.ओ.एल. एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति. ● छ.ग. वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत रुपये 20,000/- तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय के स्वीकृति के अधिकार. ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य
<p>2. श्रीमती सूर्य किरण तिवारी अग्रवाल, रा.प्र.से., संयुक्त कलेक्टर.</p>		<p>प्रभारी अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सिटी मजिस्ट्रेट ● भू-अभिलेख शाखा ● FRA एवं FCA प्रमाण पत्र जारी करने व उससे संबंधित प्रकरणों को निराकरण करने हेतु. ● सहायक अधीक्षक सामान्य/राजस्व आपदा प्रबंधन शाखा एवं कोविड 19 के प्रकरण (संबंधित शाखा की समस्त नस्ती अनुमोदन हेतु नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे.) ● सहायक अधीक्षक राजस्व व कार्यालय निरीक्षण ● भू-अर्जन/पुनर्वास ● रेल कारीडोर परियोजना ● भू-बंटन ● छ.ग. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 ● जनगणना ● जिला पर्यावरण संरक्षण मण्डल (पर्यावरण) ● यातायात जिला सड़क सुरक्षा ● लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर समय पर तैयार कर नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. ● भू-बंटन ● लायसेंस शाखा/शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण से संबंधित नस्ती स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे. ● जन सूचना अधिकारी-कार्यालय कलेक्टर कोरबा ● समय-सीमा बैठक की संपूर्ण जानकारी

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> ● आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के द्वारा ली जाने वाली मिटिंग एवं अन्य मिटिंग हेतु संधारित होने वाली जानकारी भेजना.
		<p>नोडल अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जिले में समय-समय में होने वाली मेगा कैम्प आयोजन हेतु. ● लाईवलीहुड कालेज. ● नगर एवं ग्राम निवेश. ● (जिला शहरी विकास अभिकरण) डूडा. ● परिवहन विभाग ● जिला पंजीयक ● उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ● समाज कल्याण विभाग एवं दिव्यांग ● औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ● जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ● जल संसाधन विभाग ● सार्वजनिक उपक्रमों से समन्वय संबंधी कार्य ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.
3.	श्री अवध सिंह राणा, रा.प्र.से. संयुक्त कलेक्टर	<p>प्रभारी अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सामान्य निर्वाचन ● स्थानीय निर्वाचन ● विभागीय जांच ● प्रपत्र लेखन एवं मुद्रण (प्रपत्र शाखा) ● अल्प बचत ● प्रतिलिपि शाखा ● अभिलेख प्रकोष्ठ (राजस्व एवं आंग्ल) ● आवक जावक ● बैंक से संबंधित समस्त कार्य (लीड बैंक नोडल) ● स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ● 20 सूत्रीय 15 सूत्रीय ● दंगा पीड़ित 1984 ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य
4.	श्री भरोसा राम ठाकुर, रा.प्र.से., डिप्टी कलेक्टर	<p>प्रभारी अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वित्त एवं स्थापना ● जिला नाजिर शाखा ● नजूल शाखा ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य
5.	श्री संजय कुमार मरकाम, रा.प्र.से., डिप्टी कलेक्टर	<p>प्रभारी अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● शिकायत शाखा :— <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य सचिव/सामान्य प्रशासन/विभिन्न विभागों के सचिवों, आयुक्त, समस्त आयोग, जनता, स्थानीय स्तर/विविध (अन्य) से प्राप्त शिकायत. ● विशेष कक्ष (प्रधानमंत्री, मु.मंत्री जनदर्शन (आनलाईन) अन्य मंत्री से प्राप्त शिकायत) ● व्यवहारवाद शाखा

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> ● सांख्य लिपिक ● चरित्र सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी ● राजस्व आंकिक ● दस्तावेज प्रमाणित शाखा ● परीक्षा शाखा ● वरिष्ठ लिपिक एवं अति वरिष्ठ लिपिक ● मुख्यमंत्री घोषणा ● नवोदय विद्यालय ● केन्द्रीय विद्यालय ● हेल्प डेस्क ● सिटीजन हेल्पलाईन ● पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति ● अकांक्षी जिला (नोडल अधिकारी) ● रेंट कंट्रोल ● शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना ● नापतौल विभाग ● तम्बाकू उत्पादन अधिनियम 2003 ● ऋण भारमुक्त प्रमाण पत्र ● छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 ● उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य

टीप :-

1. जिला कोरबा के अनुविभाग कटघोरा, पोड़ीउपरोड़ा एवं पाली के अंतर्गत तहसील कटघोरा, पाली, पोड़ीउपरोड़ा, दर्री एवं हरदीबाजार के छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में की जावेगी.
2. हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी के प्रकरणों में सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में की जावेगी.
3. अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम जिला कार्यालय कोरबा के प्रकरणों में सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में की जावेगी.
4. अन्य समस्त विषय/मामले जो किसी भी अधिकारी को आर्बिट्रिट न हो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा द्वारा सम्पादित किया जावेगा.
5. जिन मामलों में कलेक्टर के Personal Designation अधिकार प्रत्यायोजित हैं, वे सभी नस्तिर्यां कलेक्टर को प्रस्तुत होंगी.
6. राज्य शासन व उच्चाधिकारियों को अभिमत भेजे जाने वाले समस्त पत्र कलेक्टर के माध्यम से भेजे जावेंगे.
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा तथा अपर कलेक्टर अपने-अपने प्रभार के सभी कार्यों का समय-समय पर मॉनिटरिंग करेंगे तथा कलेक्टर को अवगत करायेंगे.
8. सभी शाखाओं के स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदस्थापना, शासन एवं उच्चाधिकारियों को भेजे जाने वाले अर्द्ध शासकीय पत्र नीतिगत मामलों एवं वरिष्ठ कार्यालयों को अभिमत भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों की नस्तिर्यां अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी.

9. सभी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अपने-अपने अनुभाग के भाड़ा नियंत्रण अधिकारी एवं लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत सक्षम अधिकारी होंगे.
10. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा की अनुपस्थिति की दशा में कलेक्टर कोरबा के चालू प्रभार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा रहेंगे.
11. जिला मुख्यालय में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/आयुक्त, नगर पालिक निगम/अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की दशा में लिंक ऑफिसर की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

क्र. (1)	अधिकारी का नाम व पदनाम (2)	संयोजन अधिकारी का नाम (3)
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा	आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा
2.	आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा
3.	श्री सुनील कुमार नायक, संयुक्त कलेक्टर कोरबा	श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर कोरबा
4.	श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर कोरबा.	श्री सुनील कुमार नायक, संयुक्त कलेक्टर कोरबा
5.	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर कोरबा	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर कोरबा
6.	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर कोरबा	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर कोरबा
7.	श्री संजय मरकाम, डिप्टी कलेक्टर कोरबा	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर कोरबा

12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा की अनुपस्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा के चालू प्रभार में रहेंगे.
13. यदि किसी कारणवश प्रभारी/लिंक अधिकारी मुख्यालय में उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित अधिकारी कार्य संपादित करेंगे.
14. उक्त संयोजन अधिकारी केवल कलेक्टर कार्यालय के शाखाओं के लिए ही रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

हस्ता./-
कलेक्टर.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1893.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे, श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, श्री ओम प्रकाश सिंह एवं सुश्री नीरा देवी सोनवानी, जिला-बिलासपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/30/2018, दिनांक 02 जुलाई, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(के. सी. देवसेनापति)
अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 2 जुलाई, 2021—11 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/30/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, जो छत्तीसगढ़ के 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 189/निर्वा.पर्य./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय चेतना शक्ति पार्टी के अभ्यर्थी श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, म.नं.-116, कोटवारपारा सकोला, कोटमी कला, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/30/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 30-Bilaspur Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Ashish Kumar Srivastav, a contesting candidate of Bhartiya Shakti Chetna Party from 30-Bilaspur Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Ashish Kumar Srivastav, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 Sh. Ashish Kumar Srivastav, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Ashish Kumar Srivastav, on 25th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that Sh. Ashish Kumar Srivastav, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Ashish Kumar Srivastav, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Ashish Kumar Srivastav, resident of H. No. 116, Kotwarpara, Sakola Kotmikala, Tah. Pendra, District-Bilaspur, Chhattisgarh and the contesting candidate of Bhartiya Shakti Chetna Party, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 30-Bilaspur Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 2 जुलाई, 2021—11 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/30/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री ओम प्रकाश सिंह जो छत्तीसगढ़ के 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री ओम प्रकाश सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री ओम प्रकाश सिंह को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री ओम प्रकाश सिंह, द्वारा 19 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 189/निर्वा.पर्य./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री ओम प्रकाश सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री ओम प्रकाश सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री ओम प्रकाश सिंह, नयापारा बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/30/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 30-Bilaspur Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Omprakash Singh, an Independent candidate from 30-Bilaspur Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Omprakash Singh, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 Sh. Omprakash Singh, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Omprakash Singh, on 19th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that Sh. Omprakash Singh, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Omprakash Singh, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Omprakash Singh resident of nayapara Bilaspur, Dist.-Bilaspur, Chhattisgarh and an independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 30-Bilaspur Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 2 जुलाई, 2021—11 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/30/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सुश्री नीरा देवी सोनवानी जो छत्तीसगढ़ के 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए सुश्री नीरा देवी सोनवानी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए सुश्री नीरा देवी सोनवानी को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस सुश्री नीरा देवी सोनवानी, द्वारा 19 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 189/निर्वा.पर्य./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुश्री नीरा देवी सोनवानी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि सुश्री नीरा देवी सोनवानी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी सुश्री नीरा देवी सोनवानी, 10/93 कुम्हारपारा, पार्श्व गली, मदरटेरेसा वार्ड, प्रोग्रेसिव विद्यालय के पास, वार्ड-10, जरहाभाठा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495001 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/30/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 30-Bilaspur Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Ms. Neera Devi Sonwani, an Independent candidate from 30-Bilaspur Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Ms. Neera Devi Sonwani, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 Ms. Neera Devi Sonwani, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Ms. Neera Devi Sonwani, on 19th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that Ms. Neera Devi Sonwani, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Ms. Neera Devi Sonwani, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Ms. Neera Devi Sonwani resident of 10/93 Kumharpara, Parsad gali, Mother Tera Ward, Near Progressive School Ward 10, Jarhabhatha, Bilaspur Chhattisgarh 495001 and an Independent Candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 30-Bilaspur Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st September 2021

No. 18/L.G./2021/II-2-20/2018.—Shri Atul Kumar Shrivastava, Additional Registrar (Administration), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 15 days from 28-07-2021 to 11-08-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 19/L.G./2021/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur), is hereby, granted earned leave for 05 days from 24-08-2021 to 28-08-2021 and permission to suffix holidays of 29th & 30th August, 2021 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 20/L.G./2021/II-2-13/2018.—Shri Pravin Kumar Pradhan, Special Judge (Atrocities), Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 21-06-2021 to 26-06-2021 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 18-06-2021 till 27-06-2021 and earned leave for 05 days from 09-08-2021 to 13-08-2021 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pradhan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 268 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 21/L.G./2021/II-2-36/2011.—Shri Ashok Kumar Luniya, the then District & Sessions Judge, Balrampur at Ramanujganj is hereby, granted earned leave for 03 days from 24-09-2020 to 26-09-2020 along with permission to remain out of headquarters from 24-09-2020 to 26-09-2020, earned leave for 03 days from 02-03-2021 to 04-03-2021, earned leave for 06 days from 21-06-2021 to 26-06-2021, earned leave for 01 day on 29-06-2021 along with permission to remain out of headquarters and commuted leave for 06 days from 26-07-2021 to 31-07-2021.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Luniya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave and 345 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 22/L.G./2021/II-3-14/2014.—Ms. Sanghratna Bhatpahari, Special Judge (Atrocities), Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 30-04-2021 to 04-05-2021.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Ms. Bhatpahari, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 23/L.G./2021/II-2-27/2016.—Shri Neeraj Sharma, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby granted earned leave for 14 days from 07-07-2021 to 20-07-2021 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 194 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 24/L.G./2021/II-3-32/2007.—Shri D.N. Bhagat, Special Judge (Atrocities), Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 26-05-2021 to 31-05-2021 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Bhagat, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 25/L.G./2021/II-3-28/2009.—Shri Santosh Kumar Aditya, II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 24-05-2021 to 26-05-2021 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 22-05-2021 till before the Court hours of 27-05-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Aditya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 274 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 26/L.G./2021/II-3-30/2008.—Shri Mohd. Rizwan Khan, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 10 days from 29-07-2021 to 07-08-2021 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Khan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+05 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 27/L.G./2021/II-2-19/2019.—Smt. Dhaneshwari Sidar, Additional Pricipal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted commuted leave for 03 days from 25-08-2021 to 27-08-2021.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sidar, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 374 days half-pay-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 28/L.G./2021/II-2-8/2021.—Shri Rajeev Kumar, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted earned leave for 37 days from 12-04-2021 to 18-05-2021 along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 04 days from 16-08-2021 to 19-08-2021 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 13-08-2021 till before the Court hours of 23-08-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajeev Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 16 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 29/L.G./2021/II-3-27/2014.—Shri Jitendra Kumar, Judge Family Court, Kondagaon is hereby, granted earned leave for 04 days from 16-02-2021 to 19-02-2021 along with permission to leave headquarters from 16-02-2021 till before the Court hours of 22-02-2021 and earned leave for 13 days from 16-08-2021 to 28-08-2021 along with permission to leave headquarters from 16-08-2021 to 30-08-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jitendra Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+02 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 30/L.G./2021/II-2-14/2015.—Shri Sudhir Kumar, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 15 days from 27-07-2021 to 10-08-2021 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 175 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2021

No. 31/L.G./2021/II-2-13/2017.—Shri Yogesh Pareek, Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 05-12-2020 to 09-12-2020 and earned leave for 05 days from 09-08-2021 to 13-08-2021 along with permission to leave headquarters after the office hours of 07-08-2021 till the evening of 14-08-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pareek, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 127 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th September 2021

No. 32/L.G./2021/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, the then Principal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 70 days from 01-05-2021 to 09-07-2021 along with permission to leave headquarters, commuted leave for 18 days from 28-07-2021 to 14-08-2021 along with permission to leave headquarters and commuted leave for 07 days from 23-08-2021 to 29-08-2021.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 191 days of earned leave & 21 days of half-pay-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 27th September 2021

No. 33/L.G./2021/II-3-46/2007.—Smt. Kiran Chaturvedi, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 10 days from 01-09-2021 to 10-09-2021 in continuation of child care leave along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Chaturvedi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 180 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 27th September 2021

No. 34/L.G./2021/II-2-28/2016.—Shri Jaideep Garg, Judge, Commercial Court (District Level), Raipur is hereby, granted earned leave for 09 days from 13-09-2021 to 21-09-2021 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 09-09-2021 till 21-09-2021.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Garg, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 143 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN.)
